सरकार ने बढ़ाई क्षमता, 99 .9 प्रतिशत इकाइयां एमएसएमई सेक्टर में हो गईं शामिल

सप्ताह का साक्षात्कार

अनिल कुमार • गाजियाबाद

बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई-नई संभावनाओं पर सरकार काम कर रही है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस प्रकार से पिछले कुछ साल में सरकार ने इस सेक्टर को बढ़ावा दिया है और लाभांवित कर निवेश सीमाओं को बढ़ाया है, उससे जिले की 99.9 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां इसी सेक्टर में अब शामिल हो चुकी है। 25 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई सेक्टर में विस्तार किया है। उन्हें सरकार ने 20 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी है। इसमें अधिकतम सब्सिडी चार करोड़ रुपये तक दी गई है। इसी कारण मैन्युफैक्चरिंग 29184 सर्विस 69358 ट्रेडिंग 24939 कुल 123481 नए पंजीयन एमएसएमई सेक्टर में हुआ है, जिसमें 13 लाख से अधिक को रोजगार हासिल हुआ। निवेश के क्षेत्र में किस प्रकार से सरकार काम कर रही है और जिला उद्योग केंद्र एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग निवेशकों का किस प्रकार से सहयोग कर रहा है। तमाम सवालों पर विभाग के उपायुक्त **अनिल कुमार** से डिप्टी चीफ रिपोर्टर **कुंदन तिवारी** के बातचीत के पेश है प्रमुख अंश:

• एमएसएमई सेक्टर को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा?

-एमएसएमई सेक्टर में माइक्रो स्तर पर उद्यम संचालित करने वाले उद्यमी जिनका प्लांट एंड मशीनरी पर एक करोड़ खर्च व वार्षिक टर्नओवर पांच करोड़ था, उसको सरकार ने प्लांट व मशीनरी पर 2.5 करोड़ और टर्नओवर दस करोड़ कर क्षमता बढ़ा दी है। इसी प्रकार स्माल स्केल पर उद्यम संचालित करने वाले उद्यमी जिनका प्लांट एंड मशीनरी पर अब तक 10 करोड़ खर्च है व वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ करने वालों की क्षमता बढ़ाकर सरकार ने प्लांट व मशीनरी पर 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ कर दिया है। मीडियम स्तर पर उद्यम संचालित करने वाले उद्यमी जिनका प्लांट एंड मशीनरी पर 50 करोड़ खर्च व वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ था, उसको सरकार ने प्लांट व मशीनरी पर 125 करोड़ व वार्षिक टर्नओवर 500 करोड़ कर दिया है।

• सरकार ने युवा उद्यमी की क्षेप तैयार करने की दिशा में क्या काम किया है?

-प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है, जिसमें किसी प्रकार की डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट हासिल करने वाले 21 से 40 वर्ष के लोगों को पांच लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो पूरी तरह से कोलैटरल फ्री है। इससे वह अपना छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर से जुड़ा कामकाज शुरू कर सकते हैं। 10 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी, छह माह के लिए ईएमआइ नहीं देना पड़ेगा। यदि किसी के पास कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें जिला उद्योग केंद्र पर प्रशिक्षण देकर इसके लाभ के लिए काबिल बनाया जाता है। अब तक 415 आवेदन आ चुके है, जिसमें से 84 युवाओं को लोन की अनुमति बैंक से मिली गई है।

• स्टार्टअप को लेकर जिले की स्थिति क्या है?

-जिले में स्टार्टअप को लेकर बेहतर स्थिति अब तक देखी गई है। 2881 स्टार्टअप के लिए पंजीयन कार्यालय पर हुआ है। हाल ही में 269 स्टार्टअप के लिए आवेदन आया है। तमाम ऐसे स्टार्टअप सामने आ चुके है, जिन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित भी किया गया है।

• तकनीकी उन्नयन योजना से अब तक कितनों को लाभान्वित किया गया?

-सरकार ने तीन वर्ष से अधिक समय से उद्यम संचालित करने वाली इकाइयों को तकनीकी अपग्रेडेशन करने के लिए तकनीकी उन्नयन योजना लांच की है, जिसमें आठ लाख रुपये तक की सब्सिडी उद्यमियों को दी जाती है। इसके लिए अब तक 100 उद्यमियों ने विभाग में आवेदन किया है। इसमें से करीब 32 को योजना के तहत फंड रिलीज कराया जा चुका है।

• क्या प्रदेश में निवेश का माहौल बन चुका है?

-इज आफ डूइंग बिजनेस में देश में प्रदेश की दूसरी रैंक मिलने के बाद से सरकार लगातार उत्साहित है। प्रदेश में निवेश का माहौल बन चुका है। देश विदेश की तमाम कंपनियां निवेश को आतुर दिख रही हैं। ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट में गौतमबुद्ध नगर से 12 लाख एक हजार 435 करोड़ के निवेश के 1973 एमओयू साइन होने के बाद यह तय हो चुका है कि प्रदेश में आर्थिक ग्रोथ इंजन के रूप में जिला रहने वाला है। यहां पर इस निवेश से अनुमानित 29 लाख 19 हजार 240 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के माध्यम से दो लाख 29 हजार 672 करोड़ रुपये के 460 परियोजना को धरातल पर उतार चुकी है। निवेशकों की 156 कामर्शियल परियोजनाओं को हाल ही में धरातल पर उतारा गया है। इसमें 85867 करोड़ के निवेश शामिल है, जिसमें एक लाख 99 हजार 414 युवाओं को रोजगार भी मिला है।

• अनुबंध करने वाले निवेशकों की परियोजनाओं को धरातल पर उतरने की लेकर क्या मानिटरिंग होती है?

-इनवेस्ट यूपी डिस्ट्रिक लेवल एमओयू इम्प्लीमेंटेशन यूनिट तैयार हुई है, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में काम कर रही है। जिला उद्योग केंद्र एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उपायुक्त सदस्य सचिव और सभी प्राधिकरण इसमें सदस्य हैं। शासन स्तर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण स्तर पर 15 टीम तैनात है, जो प्रत्येक प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वह निवेशकों से संपर्क में रह उनके दस्तावेजों को पूरा करवा रहे हैं। समस्या निस्तारण के लिए प्रत्येक माह उद्योग बंधु के रूप में बैठक हो रही है। जिला स्तर पर समस्या समाधान नहीं होने पर आइडीसी की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय कमेटी निस्तारण करा रही है। मानिटरिंग की पूरी व्यवस्था है। दो टीम जिलाधिकारी को रिपोर्ट करती है।